and if he fails to persuade the Ministry of Finance, can he seek the intervention of the Prime Minister? This is the only assurance that we want from him.

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR: I will bring it to the notice of the hon. Prime Minister.

THE DEPUTY CHAIRMAN: What will you bring? The Prime Minister is already listening to it himself.

SHRI I.K. GUJRAL: I know this issue also came up before the Consultative Committee meeting. This issue is receiving my attention.

THE DEPUTY CHAIRMAN: After an assurance, do we need further clarification?

SHRI VAYALAR RAVI: Madam, this is pertaining to *"The Hindu"* newspaper. *"The Hindu"* Newspaper is one of the major newspapers with a standing and reputation. Here the question of provocation was the intolerance of the State Government and the Chief Minister because of publication of a report. The basic thrust of the question is, intolerance of the State Government and the Chief Minister and use of muscle power and Government machinery to suffocate the newspaper - media. The hon. Minister answered that their officers visited and examined all the documents. You said that your Provident Fund Commission office records regularly all the payments without any default. In spite of having all the records in your office, why have you sent your officers to the office of *"The Hindu"* newspaper, which is having high reputation? My question is, is it not a kind of humiliation, is it not a kind of using Government machinery to humiliate a newspaper, even though the records are available in your office?

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR: Madam, inspections are conducted regularly. Conducting an inspection is not going to cast any aspersions. Secondly, I do not want to make any comment on the Chief Minister's report. ...(*Interruptions*)...

SHRI VAYALAR RAVI: Madam, it is quite irresponsible ...(*Interruptions*)... Is it not irresponsible? ...(*Interruptions*)...

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR: I do not want to comment on that ...(*Interruptions*)... What I can only say is, ...(*Interruptions*)... as far as the Labour Ministry and the Provident Commission Department are concerned , we have found out, through our inspection, that *"The Hindu"* has not committed any irregularity.

SHRI VAYALAR RAVI: You have all the records in your office. What made you to go there?

SHRI M.P. VEERENDRA KUMAR: We always update our records. You know very well that the records we have are three-month old; they are not updated records.

SHRI VAYALAR RAVI: I know everything.

THE DEPUTY CHAIRMAN: After the Prime Minister's assurance, I will move on to Question Number 122.

दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली की नियमित कालोनियों हेतु मांगी गई राशि

*122. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् दिल्ली की अनेक अनधिकृत कालोनियों को नियमित कर दिया है और इन कालोनियों में विद्युत, पेयजल, सीवर लाइन, सड़कें इत्यादि जैसी मूल सुविधाएं प्रदान करने के प्रयोजन से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव में कितनी कालोनियों को शामिल किया गया है तथा इनके नाम क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव के अनुसार कितनी राशि दी गई है अथवा दिए जाने का विचार है;

(घ) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन कालोनियों में उक्त मूल सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा० यू० वेंकटेश्वरलू) (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री महेश्वर सिंह: महोदया, यह बात सर्वविदित है कि दिल्ली में मोलड़ बंद एक्सटेंशन बदरपुर बार्डर, नयी दिल्ली साउथ में हजारों इस प्रकार की कालोनियां हैं जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में बदली है। यह आज नहीं बदली है, ये वर्षों पहले बदली है। यह उस समय से है जब दिल्ली में विधान सभा नहीं थी। इसका दायित्व उस समय की सरकार का बनता था कि वह समय रहते इस प्रकार की अवैध कालोनियों के बारे में उचित कार्यवाही करती। समय रहते ऐसा न कर अब इन कालोनियों में बसे लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विरासत में मिली इन अवैध कालोनियों के बारे में और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए दिल्ली सरकार ने 31 मार्च, 1993 तक बसी लगभग 1073 कालोनियों को नियमित करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है और उस प्रस्ताव में यह भी मांग की है कि इन लोगों को मूलभूत सुविधायें प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए क्योंकि इस भूमि की मालिक केंद्रीय सरकार है न कि दिल्ली सरकार। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने यह प्रस्ताव आप को कब भेजा है और इस प्रस्ताव पर भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या भारत सरकार की मंशा नारकीय जीवन व्यतीत करने वाले इन लोगों को मूलभूत सुविधायें प्रदान करने की है या नहीं?

DR. U. VENKATESWARLU: Madam, the question of regularisation of the unathorised colonies in Delhi is really a very lengthy story and is really bothering every agency - Delhi local bodies, Delhi Government and more particularly, the Union Government. From the moment the Delhi Government took over in 1993, it has taken up the issue of regularisation of unathorised clonies in all earnestness.

It had proposed in the months of May-June, 1993 to regularise 1071 unathorised colonies. Even prior to that, based on the directions of the Union Government, in 1977 a notification was issued to regularise 567 colonies. They were all regularised and basic civic amenities were provided to them to the maximum possible extent. But, subsequently the Government of NCT of Delhi has proposed for further regularisation of 1071 colonies. The matter has gone to the High Court. It is *sub judice*. The High Court has not yet given clearance for regularisation of these 1071 colonies. A high-powered committee was also constituted to go into details. It has provided the required data. But, the matter is still pending before the High Court.

श्री महेश्वर सिंह: उपसभापति महोदया, जैसे कि मंत्री महोदय ने कहा कि यह मामला अब उच्च न्यायालय में लम्बित है, मेरी जानकारी के अनुसार जब दिल्ली सरकार ने इन कालोनियों में अपने सीमित साधनों से मूलभूत सुविधाएं देने का प्रयास किया तो दिल्ली के कुछ व्यक्ति और कुछ संस्थाएं इस मामले को ले कर हाई कोर्ट में गई। उनका कहना यह है चूंकि इन कालोनियों से सरकार को कोई हाऊस टैक्स नहीं मिलता और कोई अन्य टैक्स भी नहीं मिलता इसलिए कोई पैसा वहां पर मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए खर्च नहीं किया जाए। जैसे कि मंत्री महोदय ने कहा कि फलस्वरूप हाई कोर्ट के आदेश से आपके शहरी विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनी और उस समिति ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। मेरी जानकारी के अनुसार एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने तो अपना ऐफिडेविट दे दिया है और जो-जो सरकार कर सकती है उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए कह दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने भी इस समिति की सिफारिश के अनुसार अपना ऐफिडेविट हाई कोर्ट में दिया है या नहीं दिया है? मंत्री जी कृपा कर के यह स्पष्ट करें। क्या उस ऐफिडेविट में आपने यह क्लीयर किया है कि मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए आप कोई धनराशि देने के लिए तैयार है या नहीं?

DR. U. VENKATESWARLU: Madam, as far as this matter is concerned, affidavits were submitted to the High Court by the MCD, the Government of NCT of Delhi and the Government of India. So, we are very active. We have been filing affidavits from time to time, and we are waiting for final judgement.

Another very pertinent issue, raised by the hon. Member, is regarding providing

water and electricity to unauthorised colonies. In this regard, the MCD had sought clarification from the High Court of Delhi vide writ petition No. 4771/93. The hon. High Court—in its order, dated 19.8.94—clarified that if the rules and regulations of the local bodies allow them, the same may be done. However, at the same time, it was made clear that providing water and electricity to these colonies would not mean regularisation of these colonies. Despite all this, the MCD and the Government of NCT of Delhi have spent Rs. 142.38 crores and Rs. 77.78 crores respectively, on these colonies. But, as per the directions of the High Court, even the provision of electricity, water, etc. would not enable them to claim regularisation.

श्री रामदास अग्रवाल: उपसभापति महोदया, माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं क्योंकि इस प्रकार की परिस्थिति, जिसमें ऐसी कालोनी, वहां हजारों निवासी रह रहे हैं और हम सब जानते हैं कि अनअथोराइज कालोनी बनती चली गई, बनती चली गई, हर राज्य में बनती चली गई, अब उनमें रहने वालों के जीवन के लिए जो स्टैंडर्ड आवश्यक है, उनके जीवन की उपयोगिता के लिए, उसको उपलब्ध कराना किसी भी सरकार के लिए आवश्यक होता है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर कुछ लोग जानबूझ कर किसी कोर्ट में चले गए तो क्या कोर्ट आऊट आफ द कोर्ट सैटलमेंट करने के लिए तैयार नहीं हो सकती? क्या कोर्ट के बाहर इन मामलों में सेटलमेंट नहीं हो सकती? कोर्ट में मामले जाने के बाद बहुत समय लगता है, यह बात हम सभी जानते हैं। तो उस समय तक, जब तक कि कोर्ट का निर्णय न आए, तब तक क्या आऊट आफ कोर्ट सेटलमेंट कर वहां के निवासियों को आवश्यक सेवाएं हम उपलब्ध नहीं करा सकते? क्या सरकार इस पर विचार नहीं कर सकती?

SHRI I.K. GUJRAL: Madam, I take the recommendation made by the hon. Member well. I respond to it positively. We will look into it.

*123. [*The Questioner (Shri Gyan Ranjan) was absent. For answer, vide Col.....infra.*]

Urban Water Supply Schemes in Maharashtra

*124. SHRI MUKESH R. PATEL:
SHRI SANJAY NIRUPAM:†

Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) the details of the urban water supply schemes submitted to Government by the Maharashtra Government;

(b) how many such schemes have been approved and how many are awaiting approval; and

(c) what are the reasons for delay in approving the schemes?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DR. U. VENKATESWARLU): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The details of the urban water supply schemes submitted to the Union Government by the Government of Maharashtra for Central assistance under the Accelerated Urban Water Supply Programme (AUWSP) for towns having population of less than 20,000 as per 1991 census and for technical approval of schemes under the State Plan/LIC loan assistance are given in Annexures I & II respectively. (*See* below)

(b) 10 water supply schemes mentioned at Sl. Nos. 1-10 in nnexure-I under the AUWSP have been approved for the State of Maharashtra for Central assistance. The remaining 19 water supply schemes have not been approved so far for want of sufficient funds under the AUWSP.

As regards 9 urban water supply schemes submitted by the State Government for technical approval

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Sanjay Nirupam.